International Journal of Multidisciplinary Trends

**E-ISSN:** 2709-9369
**P-ISSN:** 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2024; 6(3): 45-51
Received: 21-01-2024
Accepted: 25-02-2024

सुनील कुमार
सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, रजत कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

**Corresponding Author:**
सुनील कुमार
सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, रजत कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

# ई-शिक्षा: प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण मे उभरता एक प्रतिमान

## सुनील कुमार

सारांश
शिक्षा के सार्वभौमीकरण में समय, दूरी, भाषा जैसी कुछ बाधाएं आरंभ से ही विद्यमान रही हैं। भारत में अनेक प्रकार की विविधता पायी जाती है, इसमें भाषा की विविधता भी विद्यमान है। भारत की कुल साक्षरता दर 77 प्रतिशत है जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 84.40 प्रतिशत और महिलाओं की 71.50 प्रतिशत है। यहाँ शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 87.70 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण साक्षरता दर 73.50 प्रतिशत के लगभग है (एन.एस.ओ. रिपोर्ट)। 1971 से 2017 तक भारत के लिए औसत अनुपात 38.64 छात्र प्रति शिक्षक था। 2017 में प्रति शिक्षक 32.75 छात्र है (यूनेस्को 2017)। भारत में शैक्षिक विभाजन काफी व्यापक है। यह शैक्षिक विभाजन ही चिंता का प्रमुख कारण है। इस शैक्षिक विभाजन को भौतिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:58.81 (स्रोतः यू-डी.आई.एस.ई.) है। इस कारण, यदि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बदलाव नहीं किया गया तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की स्थिति और खराब हो जाएगी। शिक्षा के सार्वभौमीकरण से अभिप्राय सभी को अवसरों की समता एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने से है जिससे सभी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। परिणामतः कोई भी व्यक्ति शिक्षण तंत्र से बाहर नहीं रहे। आज के प्रासंगिक युग में शिक्षा एवं दक्षता समृद्धि के प्रमुख आध गारों में से एक है। वर्तमान समय में ई-शिक्षा की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण यह समाज का बहुत ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रसार ने ई-शिक्षा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

कुटशब्द: ई-शिक्षा, शिक्षा के सार्वभौमीकरण, शैक्षिक विभाजन

## प्रस्तावना
हमारा देश में वैदिक काल से शिक्षा के लिए समृद्ध रहा है। प्रारंभ में शिक्षा कुछ वर्गों तक ही सीमित थी। बौद्ध और मध्यकाल में भी शिक्षा की यही

स्थिति थी। सभी वर्गों के लिए शिक्षा की मांग 1919 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गयी थी। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, इस कारण अधिकांश देशों ने प्राथमिक शिक्षा को अपने नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार घोषित कर दिया है। बच्चों के चरित्र का विकास बचपन से ही शुरू हो जाता है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के सोचने की क्षमता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, साथ ही मौलिक मूल्यों एवं अच्छे जीवन को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्राथमिक शिक्षा न केवल एक व्यक्ति के विकास में वरन राष्ट्र के विकास में भी राहायक होती है हालांकि भारत में अधिकांश माता-पिता अच्छे स्कूल की जगह, घर से स्कूल कितना दूर है इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं यद्यपि स्कूल का चयन करते समय दूरी चयन का प्राथमिक अवयव नहीं होना चाहिए। कुछ माता-पिता स्कूल के इतिहास, गतिविधियों, पाठ्यक्रम पर ध्यान देते हैं बेशक वे अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल चाहते हैं और स्कूल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का पहला और मौलिक अधिकार है। इस कारण सरकार का ही नहीं वरन माता-पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में चेतना को जगाना, आत्म-सम्मान को बढ़ाना इत्यादि है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा बच्चों के विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय संविधान का आदेश है कि सभी बच्चों को जो 14 वर्षों तक के हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। सामान्य तौर पर, यह पता चला है कि घरेलू आर्थिक कारक बच्चों के स्कूल न जाने या स्कूल छोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान विशेष महत्त्व रखता है। यह संधीय और राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे महत्वपूर्ण कार्यान्वयन मुद्दों को दूर करें यदि नई समग्र शिक्षा भविष्य के राष्ट्र के हितधारकों को लाभान्वित करना है।

## प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व

भारत में प्राथमिक विद्यालय बच्चों को वो बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं जो उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिएआवश्यक है। यह बच्चों को सहयोग, संचार और सहानुभूति जैसे कौशल भी विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक है जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों के समग्र विकास में प्राथमिक शिक्षा का महत्व कई मायने में है।

## नैतिक मूल्य

बच्चों में नैतिक सिद्धांतों को समझने की नीव प्राथमिक शिक्षा के साथ ही शुरू कर दिया जाता है। मानक शिक्षाओं के अलावा, शिक्षक अन्य तरीकों से भी बच्चों में नैतिक चरित्र का विकास करते हैं जो उनके समग्र विकास, चरित्र-विकास और उचित मार्ग चुनने में सहायता प्रदान करते हैं।

## सामाजिक विकास

स्कूल वो जगह है जहां से बच्चों का अधिगम प्रारंभ होता है। बच्चे यहाँ सहपाठियों और शिक्षक सहित विभिन्न नए लोगों से बातचीत करना सीखते हैं। इससे पहले वो अपना अधिकांश समय अपने माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों के साथ निभाते थे लेकिन स्कूल में आने के बाद वे एक नए वातावरण में प्रवेश करते हैं जहां वो एक-दूसरे के साथ जुड़ना, खेलना और साझा करना सीखते हैं।

## पढ़ने और संचार का कौशल

प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ना सीखते हैं और इसी के साथ वो संवाद और संचार भी सीखते हैं। पढ़ने का कौशल जीवनपर्यन्त फायदेमंद है। यह बच्चों के देखने और कल्पना करने की क्षमता को भी विकसित करता है।

आत्मविश्वास का विकास

जब एक बच्चा अच्छे प्राथमिक विद्यालय में जाना शुरू करता है तो वो एक सकारात्मक वातावरण के संपर्क में आता है जिसमें शिक्षकों द्वारा उनका अच्छे से मार्गदर्शन किया जाता है। स्कूल का सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण सीखने औरआत्मविश्वासी बनने में सहायता करता है।

ई-शिक्षा

ई-शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराना। ई-शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल है। यह अधिगम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें वेबसाइट के माध्यम से कंप्यूटर पर शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। यह शिक्षा को तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक दोनों स्वरूपों में उपलब्ध कराता है। ई-शिक्षा अध्ययन सामग्रियों को अंतरजाल के माध्यम से अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरे शब्दों में इसे संगणक इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण या इंटरनेट शिक्षण भी कहते हैं जो दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने में भी बहुत सहायक है। ई-लर्निंग को शिक्षा के ऐसे माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी सहायता से शिक्षा को 'कहीं भी' 'किसी भी समय' उपलब्ध कराया जा सकता है। ई-शिक्षा द्वारा परंपरागत कक्षा-शिक्षण की व्यापकता को बढ़ाने के किए इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अल्बर्ट आइन्सटाइन ने कहा है कि "शिक्षा वह है जो किसी के भूल जाने के बाद बची रहती है जो एक स्कूल में सीखा है। ई-शिक्षा उन लोगों को अध्ययन और पुनः शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध कराता है जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं और पुनः स्कूल जाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जिन संस्थानों में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है वहाँ शिक्षकों द्वारा छात्रों का मूल्यांकन संगणक द्वारा आसानी से हो जाता है। ई-शिक्षा के हर-वर्ग, हर-व्यक्ति को घर बैठे अपने अधिगम को सतत बनाए रखने में मदद करता है। जहां एक तरफ ई-शिक्षा, अधिगम को आडिओ-विडिओ के रूप सभी की आसान पहुँच को सुनिश्चित करता है वहीं कई मामलों में यह शिक्षा प्रदान करने में शुल्क का प्रावधान भी करता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अनलाइन शिक्षा बाजार का व्यापार आरंभ में 20 अरब डॉलर तक था जो 2017 तक 40 अरब डॉलर तक पहुँच गया था। जहां एक तरफ ई-शिक्षा की अवधारणा का विरोध करने वाले यह तर्क रखते हैं कि शिक्षा की यह पद्धति जो ज्ञान प्रदान करती है उसमें सूचना और ज्ञान का अभाव होता है वहीं दूसरी ओर शिक्षा प्रदान करने की इस नवीन पद्धति का समर्थन करने वाले संगणक और अन्य ई-सामग्रियों को स्व-अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण और प्रेरित करने वाला मानते हैं। यह अपने 'कहीं भी" "किसी भी' जैसी खूबियों के कारण, वयस्क शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी एवं प्रासंगिक है।

यह उन राष्ट्रों के लिए विशेष रूप प्रासंगिक है जहां शिक्षा ग्रहण बहुत खर्चीली है, तकनीकी काफी महंगी है, अवसर और संसाधन सीमित हैं, साथ ही बहुत ज्यादा आर्थिक असमानताएं विद्यमान हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली सम्पूर्ण विश्व में सबसे वृहद शिक्षा प्रणाली में से एक मानी जाती है जिसमें 10 लाख से अधि एक स्कूल और 1800 हजार से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों का नेटवर्क शामिल है। नीतियों, प्रक्रियाओं, उत्पाद, सूचना-दस्तावेजों, रिपोटों, प्रस्तुतियों और प्रस्ताओं की विशेषज्ञता जैसी जानकारियाँ सामान्यतः प्रपत्रों में दर्ज की जाती हैं।

ई-लर्निंग के प्रकार

स्थिर ई-शिक्षा: स्थिर ई-शिक्षा आनलाईन सीखने के पुराने संस्करणों में से एक है। यह सीखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो छात्रों की जानकारी देने की पारंपरिक संरचना का उपयोग करता है। इस पद्धति द्वारा शिक्षार्थियों को वही जानकारी प्राप्त होती है जो प्रशिक्षकों द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं चूँकि शिक्षण सामग्री प्रशिक्षकों पर निर्भर करती है इसलिए कठोर है और छात्रों की प्राथमिकताओं के अनुकूल नहीं है।

अनुकूल ई-शिक्षा: अनुकूल ई-शिक्षा एक अन्य प्रकार की आनलाईन शिक्षा है जिसको इस तरह निर्मित किया गया है जिसमें शिक्षण सामग्रियों को बच्चों के सीखने की प्राथमिकताओंके अनुकूल हो, इस कारण यह लचीली है।

तुल्यकालिक ई-शिक्षा: यह शिक्षण प्रणाली वास्तविक समय संचार प्रणाली पर आधारित है शिक्षार्थी और शिक्षक एक ही समय पर आनलाईन एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। इसमें संगणक या मोबाईल पर संचार तकनीकी की सहायता से अनुदेशक और सहभागी एक ही समय पर शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।

अतुल्यकालिक ई-शिक्षा: इस शिक्षण प्रणाली में शिक्षार्थी और शिक्षक या प्रशिक्षक और सहभागी भिन्न-भिन्न समय में शिक्षण, प्रशिक्षण या कक्षा का सम्पादन होता है। यह सहभागिता-सूचित चार्ट पटलों, ब्लाग और ई-मेल के माध्यम से हो सकती है। अतुल्यकालिक ई-शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी किसी भी वक्त शिक्षण-प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक और शिक्षार्थियों का एक साथ परस्पर विचार-विमर्श आवश्यक नहीं होता।

व्यक्तिगत ई-शिक्षा: व्यक्तिगत ई-शिक्षा द्वारा छात्र बिना किसी की सहायता लिए स्वयं से सीखते हैं।

संवादमूलक ई-शिक्षा: इस शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकते हैं जिसके कारण शिक्षण सामग्री दोनों के मिले-जुले प्रयासों से निर्मित होती है अतः यह भी स्वभाव में लचीली होती है। यह सीमित और घनिष्ट समूह के लिए अधिक उपयोगी है।

सहयोगी ई-शिक्षा: यह ई-शिक्षा सामूहिक कार्य पर केंद्रित होती है जिसमें छात्र एक साथ काम करते हैं। शिक्षण सामग्री को बनने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। इस शिक्षण प्रणाली में खुद की और अपने समूह के लोगों की क्षमतों को ध्यान में रखकर कार्यों का निर्वहन किया जाता है।

ई-शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

ई-शिक्षा 1999 अस्तित्व में आयी। ई-शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग पहली बार सी.बी.टी-संगोष्ठी में किया गया था। ई-शिक्षा का उदय एक दिन में नहीं हो गया, और यह विकास शनैः-शनैः हुआ है और इसी के साथ आनलाइन-शिक्षा और वर्चुअल (आभाषी) शिक्षा जैसी संकल्पनाओं का भी जन्म हुआ। ई-शिक्षा को मूलतः छात्रों या शिक्षकों शिक्षा सामग्रियों को वितरित करने की उद्देश प्रतिपूर्ति के लिए किया गया था लेकिन बाद में यह प्रणाली परस्पर प्रतिक्रियात्मक हो गयी। ई-शिक्षा के उदय के पूर्व दूरस्थ शिक्षा के संचालन में डाक पद्धति का उपयोग किया जाता था जहां शिक्षण-सामग्रियों को डॉक द्वारा भेजा जाता था। अध्यापकों एवं पथ प्रदर्शकों के साथ परस्पर-प्रक्रिया पत्राचार या डॉक-पत्रों के माध्यम से ही होती थी।

टी-अधिगम

टी-शिक्षा वर्तमान में एक उभरती हुयी संकल्पना है। टी-अधिगम द्वारा उच्च मूल्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा को "कभी भी' 'कहीं भी" प्रदान करने में सहायक है। टी-अधिगम, शिक्षण-सेवाओं और प्रौद्योगिकी का संयोजन है। टी-अधिगम को शिक्षा-व्यवसाय के विकास और डिजिटल अभिसरण के विकास का अगला चरण के रूप में उदयित हुआ है। टी-अधिगम अपने बेहतर और प्रभावशाली ढंग से वृद्धि करने के लिए शोध और अनुप्रयोगों की आवश्यकता है। यह केंद्रित और प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। वर्तमान में इसके द्वारा कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण-प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका में सहायक है।

एम-अधिगम

एम-लर्निंग का अभिप्राय है- 'मोबाइल द्वारा अधिगम "शिक्षा, सूचनाओं, अध्ययन-सामग्रियों, प्रशिक्षण को ऑनलाइन "कभी भी" "कहीं भी उपलब्ध कराना ही

मोबाइल-अधिगम है। मोबाइल अधिगम उन कार्मिकों तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध कराने में भी सहायक हैं जो हमेशा भाग-दौड़ वाला काम करते हैं या दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्यों का निर्वहन करते हैं।

प्रतिमान विस्थापन

प्रतिमान विस्थापन से क्या अभिप्राय है? शायद, निर्माण क्षेत्र का विश्लेषणातमक अध्ययन प्रतिमान विस्थापन को समझने में सहायक है। जहां यह अभी भी प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे उत्पन्न चुनौती को गुणवत्ता और सेवाओं का प्रभावी ढंग से विनियमन करना ही सहायक हैं। प्रतिस्पर्धता में बने रहने के लिए गुणवत्ता, संतुष्टि आवश्यक अवयव हैं। यहाँ संतुष्टि का अभिप्राय शिक्षक-शिक्षार्थी संतुष्टि से हैं। यदि प्राथमिक शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो इसका असर कॉलेज और विश्वविद्यालय पर भी दिखेगा सामान्यतः ऐसा वर्तमान शिक्षा प्रणाली से असंतोष के कारण होता है।

सामान्य शिक्षा और व्यसायिक शिक्षा का तुलनात्मक अध् ययन करें तो सामान्य शिक्षा वर्तमान के प्रासंगिक समाज में तालमेल बनाने में विफल हो रही हैं। सामान्य शिक्षा आज भी परंपरागत पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हैं और परंपरागत मानसिकता का निर्धारण करता है। सामान्यतः ऐसी धारणा है कि सामान्य शिक्षा की पाठ्यक्रमों की सामग्री, भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए सहायक नहीं हो सकती हैं। वर्तमान युग सूचना-आधारित ज्ञान-युग है जहां ज्ञान आधारित कार्यों द्वारा धनोपार्जन का कार्य किया जाता है। ज्ञातव्य है कि परंपरागत उद्योगों में निवेश के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है वहीं ज्ञान-आधारित उद्यमों में ज्ञान-श्रमिकों के रूप में मानव पूंजी की आवश्यकता होती हैं।

संगणक में बड़ी मात्रा में सूचनाओं का आसान और व्यवस्थित रूप में संग्रहण किया जा सकता है। संगणक की खुद की कोईसोच नहीं होतीं। यह अपनेउपयोगकर्ता के निर्देशन में हीकार्यों का सम्पादन करता है। सतत और निरंतर प्रयासों एवं संसाधनों के उचित दोहन से ही कम पूंजी के साथ, कम समय में बहुत ज्यादा सफलता हासिल की जा सकती हैं। इसलिए शिक्षा की प्रणाली कोई भी हो लचीली हो, वर्तमान प्रसंगिकताओं के अनुकूल हो, सोच और कौशल विकसित करने के अनुकूल हो, साथ ही उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए, जो शिक्षार्थियों में सीखने की क्षमता और ललक के लिए प्रेरित करती रहे अन्यथा इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी।

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वर्तमान समय में छात्र, स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले परंपरागत तरीकों एवं अंग्रेजी भाषा के न्यूनतम प्रयोग, प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित करती है। इसी कारण 21वीं सदी में प्रभावी ढंग से जीने एवं युवाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, स्कूलों में शिक्षण को पुनः उन्मुख करने की तत्काल आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के समक्ष बहुत सी चुनौतियों हैं जिनके उत्कृष्ट समाधान के लिए मौजूदा विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन आवश्यक है। इतिहास से हमने सीखा है कि विकल्पों के चयन को टाला नहीं जा सकता। यहाँ विकल्पों का सर्वोत्तम चयन महत्त्वपूर्ण होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मौजूदा उपकरण, 21वीं सदी के लिए आवश्यक विकल्पों और संसाधनों की प्रसंगिकताओं की कसौटी को पूरी करते हैं। जिसके लक्ष्यों में संगणक और की-बोर्ड के द्वारा पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्रियों तक सभी की पहुँच सुनिश्चित हो सके, साथ ही तुल्यकालिक-अतुल्यकालिक शिक्षण 'कभी भी' 'कहीं-भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सके।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के समक्ष चुनौतियाँ

विद्यालय से पलायन: विद्यालयों में नामांकन के बाद 'छोड़-देना' एक वृहद समस्या है। सामान्यतः यह समस्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ज्यादा पायी जाती है। कक्षा 1 से 8 तक जाते-जाते लगभग आधे बच्चे अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। (भारत में शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2012)

सामाजिक-आर्थिक कारक: सामाजिक-आर्थिक कारक शिक्षा को काफी हद तक प्रभावित करता है। जहां एक तरफ सामाजिक कारक प्रमुखतः अनुसूचित जाति और जनजातियों के संदर्भ में हैं। कुछ का मानना है कि इस समुदाय के लोग कुछ चयनित सामाजिक कार्यों के लिए है यदि वो शिक्षित होंगे तो उन आमुख कार्यों को नही करेंगे इसलिए वो शिक्षा में भेदभाव करते हैं। वहीं आर्थिक कारकों की बात करें तो गरीब परिवार अपनी 'पारिवारिक-आय' पर ध्यान देते हैं। जहां पारिवारिक आय का मतलब है परिवार के सभी सदस्य आमदनी के श्रोत होते हैं. यदि यो स्कूल जाएंगे तो परिवार की आमदनी घटेगी। इस कारण यो स्कूल नहीं जाते इसके अलावा शिक्षा एक खर्चीला उपक्रम है।

ग्रामीण नगरीय विषमता: ग्रामीण और शहरीय पृष्ठभूमि में काफी अंतर है। शहरीय लोग वर्तमान प्रासंगिकता के प्रति जागरूक होते हैं। ज्यादातर अच्छे शिक्षण संस्थान शहरों में होते हैं। यहाँ लोग अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक शिक्षा दिलाने पर जोर देते हैं। ग्रामीण लोगों को भी अच्छी और प्रासंगिक शिक्षा दिलाने के लिए शहरों का ही रुख करना पड़ता है जहां दोनों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग 67.77 प्रतिशत है वहीं शहरी क्षेत्रों में यह दर लगभग 84.11 प्रतिशत है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की लैंगिक साक्षरता दर में भी काफी विषमताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर 19.3 प्रतिशत तथा शहरीय क्षेत्रों में यह अंतर 9.1 प्रतिशत है। (मारत में शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2012)

क्षेत्रीय विषमता: क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर मी साक्षरता दर में काफी अंतर विद्यमान है। केरल (93.91), मिजोरम (91.58), लक्षद्वीप (92.28), गोवा (87.40), राज्यों में शिक्षा दर काफी बेहतर है जबकि बिहार (63.82), झारखंड (67.63), अरुणांचल प्रदेश (66.95) आदि राज्यों में शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। लैंगिक असमानता के आधार पर मिजोरम की स्थिति अच्छी है। सामान्यतः जिन राज्यों की साक्षरता दर अच्छी होती है वहीं का लैंगिक-दर भी अच्छी होती है। शिक्षा का लैंगिक विषमता के समाधान के सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है। (भारत में शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक रिथत्ति 2012)

सरकारी व्यय में कमी कोठारी आयोग (1964-66) की अनुशंसा के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने की संस्तुति की थी लेकिन अभी भी यह 4 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकी है। इस कारण प्राथमिक स्तर पर सम्पूर्ण सुविधाएं और संसाधन मुहैया नहीं कराया जा पा रहा है।

शिक्षक एवं संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव: शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय मानक से कम है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का भी अभाव है। सरकार कम मानदेय पर अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति कर, शिक्षण कार्यों का सम्पादन कर रही है। इस कारण शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। विद्यालयों में सूचना प्रसार तकनीकी का भी अभाव है जिसके कारण ई-शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

गुणवत्ता का अभाव: वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। यही कारण है कि अभिभावकों के दृष्टिकोण में प्राथमिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं है कि वो आज के युग में प्रासंगिक हो। 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, कक्षा 2 की किताबें भी नहीं पढ़ पाते। सामान्यतः प्राथमिक स्कूलों में वो ही बच्चे नामांकन करातेहैं जिनके पास शिक्षा ग्रहण करने का अन्य कोई विकल्प नहीं होता। (प्रथम, शिक्षा की स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट 2019, प्रथम, नई दिल्ली 2019)

प्रासंगिकता का संघर्ष: वर्तमान के वैश्वीकरण और उदारीकरण के समय में वही देश प्रतिस्पर्धा में बने रह सकता है जिस देश में गुणवत्तापूर्ण और कौशलपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। उच्च-शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का आधार प्राथमिक शिक्षा है। उच्च-शिक्षा तभी अपने उत्कृष्ट निष्पादन कर सकेगी जब प्राथमिक शिक्षा के

लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए. जिससे शिक्षा की नीव मजबूत बनी रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें सहयोगात्मकरण नीतियाँ अपनाएं जिससे गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके। इस संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास सराहनीय है।

## निष्कर्ष एवं सुझाव

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सरकार द्वारा सतत अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा की प्रासंगिकता को बढ़ाते हुए इसे मात्र पढ़ना-लिखना या एवं सामान्य गणित की समझा तक सीमित नया रखते हुए प्रभावी एवं जीवनोपार्जन हेतु उपयोगी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है तथा यहाँ गाँव एवं कृषि का विशेष महत्व है। इस कारण गांवों में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता पर भी ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है। हमें क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषणात्मक अनुकरण करना चाहिए। शिक्षा अपने विकास के लिए अनेकों कारकों जैसे समाज, आर्थिक स्थिति, शिक्षक की योग्यता तथा अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। भारत सरकार ई-शिक्षा को प्रभावी और सर्वव्यापी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और तकनीक विकसित कर रहा है। भारत सरकार ई-शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रयास कर रही है। ई-शिक्षा को बेहतर बनाने किए प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास जैसे प्रयास प्रमुख है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के उपभोग में वृद्धि के कारण ई-शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। वर्तमान में, ई-शिक्षा के द्वारा शिक्षण का ही कार्य हो रहा है लेकिन निकट भविष्य में इसे शोध-कार्यों तक विकसित करना है।

## संदर्भ सूची


1. Anderson T, editor. The theory and practice of online learning. Athabasca University Press; c2008.
2. Arun Gaikwad VS. E-Learning in India: wheel of change. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. 2016;6(0):1.
3. Banerjee R. An Innovative Methodology and Framework for Personalized E-Learning Using Conventional and Mobile Networking Technologies. In Proceedings of the National Seminar on E-Learning and E-Learning Technologies: ELETECH; c2001. p. 1-4.
4. Chowdhury SR, Kar G, Thakur AK, Brahmanand PS, Nayak AK, Verma OP, et al. Ministry of Human Resource Development, Government of India. Annual Report; c2013-2014.
5. Dadush D, Ducas L. Random oracle; c2018 [cited 2024 Mar 21]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Random_oracle
6. Jobirovich YM. Tools of Using Digital Technologies in Primary Educational Courses. European Journal of Modern Medicine and Practice. 2022;2(4):119-123.
7. Kumar K, Prakash A, Singh K. How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generation in India. Journal of Public Affairs. 2021;21(3):e2500.
8. Kingdon G, Muzammil M. A political economy of education in India: The case of Uttar Pradesh. Oxford Development Studies. 2009;37(2):123-144.
9. Sharma RC, Mishra S. E-learning in India. In International Handbook of E-learning, Routledge; c2015;2:223-230.
10. Tilak JB. How free is' free primary education in India? Economic and Political weekly; c1996. p. 355-366.